



न्याय साक्षी

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, शुक्रवार 08 मार्च 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-158

महत्वपूर्ण एवं खास

उत्तरी इराक में आईएस का हमला, आठ सैनिकों की मौत, 42 घायल

बगदाद (आरएनएस)। उत्तरी इराक के मखमूर में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के हमले में अर्ध सैनिक बलों के छह जवानों की मौत हो गयी तथा 31 अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षा सेवाओं की प्रेस सेवा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इससे पहले मीडिया ने बताया कि मोसुल से तुज खुरमा तक के मार्ग में आईएस द्वारा किये गए हमलों में अर्ध सैनिक बलों (अल हषद अल शाबी) के दो जवान मारे गए तथा 11 लोग घायल हुए हैं। प्रेस सेवा ने कहा, मखमूर-मोसुल राजमार्ग पर अल अषद अल शाबी (अर्ध सैनिक बलों) के काफिल पर आतंकवादियों द्वारा किये गये कारगरतापूर्ण हमले में छह जवान मारे गए तथा 31 अन्य घायल हो गये। घायलों को अल कयारह के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अमेरिका के आलस्का में भूकंप के झटके

वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिका आलस्का राज्य में बुधवार को मध्य स्तर के भूकंप के झटके महसूस किये गए। स्थानीय समय के अनुसार रात नौ बजकर 33 मिनट और 14 सेकंड पर महसूस किये गए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पर 5.4 मापी गयी।

अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 9.3 किलोमीटर की नीचे और 66.3088 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 157.1853 डिग्री पश्चिम देशांतर पर केंद्रित था।

पाकिस्तान जैश की मदद से भारत में करवाता था बम धमाके

मुशरफ का कबूलनामा

इस्लामाबाद (आरएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशरफ ने अपने ही देश की पोल खोल दी है। बुधवार को एक पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत करते हुए परवेज मुशरफ ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद का कई बार इस्तेमाल किया है। मुशरफ ने कहा, मेरे कार्यकाल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत पर हमलों को अंजाम देने के लिए कई दफा आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की मदद ली।

'सबसे साफ शहर' का सम्मान लगातार तीसरे साल इंदौर के नाम

नयी दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार तीसरे साल इंदौर को भारत के सबसे साफ शहर का दर्जा मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को यहां एक कार्यक्रम में 'द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड' 2019 प्रदान किया। नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को 'सबसे स्वच्छ छोटा शहर' घोषित किया गया। उत्तराखंड के गौचर को 'सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर' घोषित किया गया। केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ये पुरस्कार प्रदान करता है। केन्द्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने इंदौर को बधाई देते हुए कहा, 'बेहद शानदार! लगातार तीसरे साल इंदौर भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर बना।

जी-20 देशों के राजनयिकों ने की राहुल से मुलाकात

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को समूह-20 के सदस्य देशों के राजदूतों के साथ ही कुछ पड़ोसी देशों के राजनयिकों को बुधवार को यहां दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनसे चर्चा की।

नेपाल में फिर से पैर पसार रहा है कुष्ठ रोग

एजेंसी। नेपाल में स्वास्थ्य अधिकारियों को कुष्ठ रोग के फिर से सिर उठाने का डर सताने लगा है। 2018 में इसकी प्रसार दर 0.94 पहुंच जाने के बाद अधिकारी चिंतित हैं। काठमांडू पोस्ट की गुरुवार की रिपोर्ट के मुताबिक, 2009 में हिमालय राष्ट्र द्वारा बीमारी को जड़ से खत्म करने की घोषणा के बाद नेपाल को कुछ मुक्त देश का दर्जा दिया गया था। हालांकि अगर प्रसार दर कुल आबादी के एक फीसदी तक पहुंच जाती है तो देश से यह दर्जा छिन सकता है।

सुरक्षाबलों से ज़्यादा राहुल को पाकिस्तान पर भरोसा

नई दिल्ली (आरएनएस)। राफेल डील मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को अपने सुरक्षा बलों से ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा है। उन्होंने इसका जवाब देने के लिए प्रेस कांफ्रेंस करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि राहुल को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। कैंग और सुप्रीम कोर्ट ने राफेल को क्लीन चिट दे दिया है तो क्या राहुल पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहते हैं। बता दें कि गुरुवार को राफेल मामले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बयान दिया, सरकार ने एक नई लाइन निकाली है कि गायब हो गया है।



बीजेपी का पलटवार

रोजगार गायब हो गया है, 15 लाख का वादा गायब हो गया, राफेल की फाइल गायब हो गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, चौकीदार को निशाना साधा। राहुल गांधी ने बयान दिया, सरकार ने एक नई लाइन निकाली है कि गायब हो गया है।

डील की मोदी जी ने बाईपास सर्जरी की है। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी की डील की वजह से भारत में राफेल विमान लाने में देरी हुई है जिसका सबूत सबूत हम देंगे। उन्होंने ये भी कहा, फाइल में लिखा है कि पीएमओ डील में दखल दे रहा था। परिकर के पास फाइल होने की जांच कीजिए, सिर्फ पीएम ही नहीं सभी की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कहा कि वो खुद इस मामले की जांच क्यों नहीं करा देते। राहुल गांधी ने पीएम से पूछा कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो जेपीसी जांच से क्यों कतरा रहे हैं। आपको बता दें बुधवार को राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने जानकारी दी थी कि राफेल के कुछ कागजात चोरी हो गए हैं।

राफेल मामले में प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए: राहुल



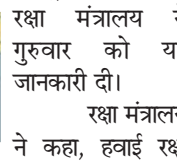
नयी दिल्ली

(आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला है और इसके लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया कि

अगर प्रधानमंत्री मोदी पाक साफ हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने कहा, 'एक नई लाइन सामने आई है-गायब हो गया। दो करोड़ रोजगार गायब हो गया। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया। 15 लाख रुपया गायब हो गया। अब जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला है और इसके लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया कि

सुखोई -27 लड़ाकू विमान ने अमेरिका के विमान को खदेड़ा: रूस

मॉस्को (आरएनएस)। रूस लौटने पर मजबूर किया। रूस के लड़ाकू विमान सुखोई -27 ने बाल्टिक सागर में उसके हवाई क्षेत्र में आए एक अमेरिकी वायु सेना के विमान का पीछा किया और उसे अपने क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, हवाई रक्षा ड्यूटी पर तैनात सुखोई -27 लड़ाकू विमान ने हमारे हवाई क्षेत्र



रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

मेरठ में एक अफवाह से भड़की हिंसा, कई गाड़ियों में तोड़फोड़

मेरठ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ते सदर इलाके में अचानक भड़की हिंसा के दौरान करीब 100 के करीब झुगियां जलकर खाक हो गईं और कई लोग घायल भी हो गए। दरअसल ये सारा मामला एक अफवाह से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि मेरठ कैंट के थाना सदर

इलाके की मलिन बस्ती में कैंट बोर्ड की टीम पुलिस के साथ अवैध निर्माण हटवाने गई थी और तभी ये बात फैल गई कि बोर्ड और पुलिस की टीम अवैध वसूली के मकसद से पहुंची है। इसके बाद इलाके के लोगों और पुलिस के बीच कहासुनी शुरू हो गई और

बात इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके के लोगों का आरोप है कि इसी दौरान पुलिस की टीम ने ही बस्ती में आग लगा दी। इसके बाद झुगियों में मौजूद गैस सिलेंडरों के फटने से यहां करीब 100

लोकपाल पर सेलेक्शन कमिटी की बैठक कब होगी दस दिन के भीतर बताए सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वह दस दिन के भीतर तय कर बताए कि वह लोकपाल पर सेलेक्शन कमिटी की बैठक कब करने जा रही है। दरअसल इस कमिटी के जरिए ही लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार से सवाल पूछने के साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रशांत

भूषण की याचिका को भी खारिज कर दिया है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि लोकपाल पर बनाई जा रही सेलेक्शन कमिटी के चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस संबंध में आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर उस आवेदन को भी खारिज कर दिया है।

जम्मू के बस अड्डे पर ग्रेनेड हमला, 18 लोग जख्मी

जम्मू (आरएनएस)। हाई अलर्ट पर चल रहे जम्मू में गुरुवार को एक बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमले के बाद ब्लास्ट होने से 18 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके को खाली कराकर जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू के आईजी मनीष सिन्हा ने बताया कि यह ग्रेनेड से किया गया हमला था। गुरुवार को भीड़-भाड़ वाले इलाके में बसे बस स्टेशन में एक बस के पास में हमला हुआ, जिसके बाद हुए धमाके की वजह से वहां पास में मौजूद 18 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में

भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। सिन्हा ने बताया, ग्रेनेड धमाका हुआ है। ऐसा लगता है कि इसे बाहर से फेंका गया है। बस में मौजूद 18 लोग घायल हुए हैं। हम लीड्स पर जांच कर रहे हैं। हमले का मकसद सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। हम जल्द ही दोषियों को पकड़ लेंगे। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार एक सिद्धि हमलावर ने ग्रेनेड से हमला किया और मौके से

फरार हो गया। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद से पूरे राज्य में हाई अलर्ट है और इसके बीच गुरुवार को जम्मू में बस स्टैंड पर हुए बम ब्लास्ट के बाद खुफिया एजेंसियों अलर्ट हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में चाइनीज ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि पहले भी यह इलाका आतंकियों के निशाने पर रहा है। फिलहाल घटनास्थल को सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया है और जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरूआती जांच में सामने आ रहा है कि इस धमाके का मकसद सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। ऐसे में प्रशासन की ओर से आगाह किया गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें।

रक्षा मंत्रालय से अहम दस्तावेज किए गए चोरी

राफेल पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदा मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने हैरानीजनक खुलासा किया है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कुछ कार्रवाई करेंगे। ये सभी बेहद अहम दस्तावेज थे। हालांकि अदालत द्वारा इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि हम इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जांच करने के बारे में सोच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि फाइल नोटिंग न्यायिक अधिनियम का विषय नहीं हो सकता है। समाचार पत्रों को राफेल से जुड़े दस्तावेज किसने दिया है, इस पर जांच जारी है। हम आपराधिक जनरल केके वेणुगोपाल ने कुछ कार्रवाई करेंगे। ये सभी बेहद अहम दस्तावेज थे। हालांकि अदालत द्वारा इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि हम इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जांच करने के बारे में सोच रहे हैं।

पति-पत्नी को यौन संबंध के लिए किया जा सकता है मजबूर ?

नई दिल्ली (आरएनएस)। अदालतें एक-दूसरे से विवाद में उलझे पति-पत्नी के बीच मेलजोल की एक और कोशिश करने के लिए कुछ मामलों में वैवाहिक रिश्ते के तहत यौन संबंध बहाल करने का निर्देश देती हैं। जो प्रावधान अदालतों को यह कदम उठाने की इजाजत देता है, उसे एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच विचार करेगी। देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने एक जज रहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भेज मसला एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान महिला विरोधी है क्योंकि यह महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध पति के पास जाने पर मजबूर करता है और



उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है। 2 छात्रों ने दाखिल की है याचिका गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ओजस्व पाठक और मयंक गुप्ता ने यह पीआईएल दाखिल की थी। उनकी ओर से दलील पेश करते हुए सीनियर ऐडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि सरसरी तौर पर यह कानून कोई लैंगिक भेदभाव करता नहीं दिखाता, लेकिन यह दरअसल बहुत पितृसत्तात्मक है और यह सामंती इंग्लिश लॉ पर आधारित है, जो

महिला को पति की निजी संपत्ति के रूप में देखता है। उन्होंने कहा, रयह संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन भी करता है। हेगड़े ने कहा कि यह लीगल प्रेमवर्क प्राइवसी, व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्ति (महिला और पुरुष, दोनों) की गरिमा का उल्लंघन करता है, जिसका अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह महिला पर बोझ लाद देता है और इस तरह यह संविधान के अनुच्छेदों 14 और 15(1) का उल्लंघन करता है। दलील: प्रावधान सामंती मानसिकता पीआईएल में कहा गया कि भारत में किसी भी पर्सनल लॉ सिस्टम में वैवाहिक रिश्ते के तहत यौन संबंध का अधिकार बहाल करने की व्यवस्था नहीं है।

यूनिवर्सिटी की नौकरियों में मिलेगा पहले जैसा आरक्षण

मोदी सरकार ने खारिज किया 13 प्वाइंट रोस्टर

नई दिल्ली (आरएनएस)। यूनिवर्सिटी की नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के नए तरीके 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दो दिन पहले ऐसे संकेत दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को 22 जनवरी को ही खारिज कर दिया था। बाद में सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी को खारिज कर दिया था। हालांकि मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लगातार कह रहे थे कि जरूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर देगी। सूत्रों के मुताबिक, 7 मार्च को मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में इस पर अध्यादेश लाने पर मुद्दा लग सकती है। सोमवार को राजस्थान के अजमेर में मौजूद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया था कि जल्दी ही अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को 13 पॉइंट रोस्टर से मुक्ति दिला दी जाएगी।